Polity

प्राक्कलन समिति [Estimates Committee]

संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

This is the largest Committee among the permanent Committees of the parliament. This Committee is formed only in the Lok Sabha. It has a total of 30 members of the Lok Sabha, members of the Rajya Sabha are not included in it.

प्राक्कलन समिति → स्थायी और वित्तीय समिति
Permanent and financial Committee

- यह संसद की सबसे बड़ी समिति है।
- इस समिति का गठन - 1950 में हुआ।
- इस समिति का गठन LS के 30 सदस्यों से होता है
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
- RS के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

इसे स्थायी प्रतिनिधित्व समिति भी कहते हैं।

सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्तमंत्री जान मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में हुआ था। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। अतः इसे 'स्थायी मितव्ययिता समिति' भी कहते हैं।

This Committee was first formed in 1950 on the recommendation of the then finance minister John mathai. It recommends to stop government wasteful expenditure. Hence, it is also called 'permanent Frugality Committee'.

लोक लेखा समिति ⟶ गठन 1919 के अधि० के अनुसार 1921 में Public Account Committee किया गया।

→ संसद की स्थायी और वित्तीय समिति
→ संसद की सबसे पुरानी समिति [oldest Comm. of parliament]
→ सदस्य संख्या ⇒ 22 (15 LS, 7 RS)
→ सदस्यों का कार्यकाल - 1 वर्ष
→ 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य बनेगा।
⇒ इसके समिति के अध्यक्ष LS अध्यक्ष द्वारा मनोनीत (Nominate) किया जाता है।
⇒ इस समिति मित्र और मार्गदर्शक (friend & guide) CAG को कहा जाता है।

लोक लेखा समिति [The public Accounts Committee]

यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से लिये जाते हैं।

This is the most important and oldest financial Committee of the parliament. It was first Constituted in 1921 Under the Government of India Act. 1919. This Committee has a total of 22 members, out of which 15 members are taken from the Lok Sabha and 7 members are taken from the Rajya Sabha.

लोकसभा अध्यक्ष, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। 1967 से स्थापित परम्परा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है। CAG को लोकलेखा समिति का मित्र व पथप्रदर्शक भी कहा जाता है

The Lok Sabha Speaker nominates the Chairman of the public Accounts Commitee. (According to the tradition established since 1967, a member of the opposition is made the chairman of this Committee. its tenure is one year. its main objective is to bring the misuse and irregularities of public expenditure before the parliament. CAG is also called the friend and guide of the public Accounts Committee.

सरकारी उपक्रम समिति [The Committee on public Undertakings]

सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर उक्त समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

Firstly in 1964, krishna Menon Committee was formed. On whose recommendation the above Committee was formed. This Committee has a total of 22 members. Out of which 15 members are from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha, its tenure

is of one year. Lok Sabha Speaker appoints one of the Lok Sabha members as the Chairman of the Commitee.

Note → प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को इनके कार्यों के कारण "जुड़वा बहन" कहा जाता है।

राज्य विधान मण्डल [The State Legislature]

संविधान के, अनु॰ 168 - 212 राज्यों के विधानमण्डल के बारे में है। अनु॰ 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

Part 6 of the Constitution, Articles 168 - 212 deals with the state legislature. Article 168 states that each State will Consist of two houses and other states will Consist of one house.

Art. 168 → राज्य विधानमंडल का निर्माण [Formation of State legislature → ① विधानसभा (Legislative Assembly)

केवल 6 राज्यों में तीन अंग वाला और 2 सदनों वाला विधान मंडल है। ⟸ ② विधानपरिषद् (" Council)

③ राज्यपाल (Governor)

⇒ क्योंकि विधानपरिषद् केवल 6 राज्यों में है।

1. U.P
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र
5. आंध्र प्रदेश
6. तेलंगाना

⇒ 22 राज्यों में (इन राज्यों के अलावा) ⇒ विधानमंडल → विधानसभा (LA), राज्यपाल (Governor)

Art. 169 ⇒ विधानपरिषद् का सृजन (Create) और अंत करना संसद की शक्ति है।

⇒ विधानपरिषद् (LC) → सृजन / अंत

⇒ विधेयक (Bill) → उस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा में पेश (Introduced) जहां इसका सृजन / अंत करना है।

⇒ विधेयक पर चर्चा (Debate on bill)

→ पारित (Pass) ⇒ विशेष बहुमत (2/3 Majority)

→ संसद के पास जायेगा।

↳ साधारण बहुमत इसे संसद द्वारा पारित करके उस राज्य में जहां विधानपरिषद् को बनाना है या नष्ट करना है, कर दिया जायेगा।

विधानपरिषद् का अंत तो किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता

वर्तमान में कुल 6 राज्यों यथा: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना

rojgar with ankit

द्वितीयक विधानमण्डल है। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनु० 169 के अन्तर्गत संसद को है।

At present, a total of 6 States Viz. Uttar pradesh, Bihar, Maharashtra, Andhra pradesh, Karnataka and Telangana have bicameral legislature. Under Article 169, the parliament has the right to establish or abolish the Legislative Council in the States.

यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है।

If the Legislative Assembly of the Concerned State passes a resolution to this effect by a majority of its total membership and a two-thirds majority of the members present and Voting.

तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है।

So the parliament can establish or abolish the legislative Council by making a law to that effect through the process of ordinary law making. making such a law is not considered as a Constitutional amendment.

* विधानसभा (Legislative Assembly)
  - Art. 170 → विधानसभा का गठन (Composition of LA)

⇒ अधिकतम सदस्य (Maximum members) = 500

⇒ न्यूनतम सदस्य (Maximum members) = 60
  - अपवाद (exception) ⇒ गोवा ⇒ 40
    मिजोरम ⇒ 40
    सिक्किम ⇒ 32
    पुदुचेरी ⇒ 30 → U.T's

⇒ सबसे बड़ी विधानसभा U.P की है।

विधानपरिषद् → केवल 6 राज्यों में

विधानसभा → 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश

(1) दिल्ली
(2) पुदुचेरी
(3) JK

* संरचना या गठन (Composition)

राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिक से अधिक 500 और कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी) परन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुदुचेरी इसके अपवाद हैं जिनकी विधान सभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40, 40, तथा 30 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की (403) है।

The State will Consist of a maximum of 500 and a minimum of 60 members elected by direct election from territorial Constituencies) but the exceptions are Sikkim, Mizoram, Goa and puducherry whose legislative assemblies have a number of member of 32, 40, 40 and 30 respectively. The largest assembly is that of Uttar pradesh (403).

सदस्यों का निर्वाचन [Election of members]

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है

It is done through direct election System. Election of State legislative assemblies is Conducted by the Election Commission of India

rojgar with ankit

84 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा
84 th Constitutional Amendment Act 2001

⇓
LS/VS/RS/VP की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक निश्चित कर दी गयी है।